

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

1. एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2097/2024

रामेश्वर पुत्र बालचंद, निवासी रावली रामगंजमंडी जिला कोटा (राज.)।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से

----- प्रतिवादी

निम्न से सम्बंधित

2. एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1978/2024

कैलाश गरवाल पुत्र गवरिया गरवाल, निवासी खड़न, पोस्ट कोदरा, पुलिस स्टेशन रवती, जिला रतलाम (म.प्र.)

----- याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से

----- प्रतिवादी

3. एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6030/2023

श्री यूनिस पुत्र साबू खान, निवासी अनह गेट, बजरिया, भरतपुर, पुलिस स्टेशन अटलबंध, भरतपुर,

(वाहन के पंजीकृत मालिक)।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से।

----- प्रतिवादी

4. एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1941/2024

जफर कुरैशी पुत्र पशु कुरैशी, निवासी फुलंबरी, जिला औरंगाबाद। (वाहन ट्रक संख्या एमएच 20 ईएल 9524 के मालिक)

----- याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से

----- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री दुष्यंत सिंह नारुका
श्री अनंत शर्मा के साथ
श्रीमती सुनीता मीना,
श्री अंकित खंडेलवाल
श्री जिया उर रहमान

न्याय मित्र (Amicus Curiae) : श्री अनुराग शर्मा
श्री एस.एस. होरा
श्री पंकज गुप्ता
श्री सुधीर जैन
श्री रजनीश गुप्ता

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री एस.एस. महला,
लोक अभियोजक

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

निर्णय

आरक्षित तिथि : 15 मई, 2024

घोषणा की तिथि : 01 जुलाई, 2024

न्यायालय द्वारा:

रिपोर्ट करने योग्य

1. इन याचिकाओं को दायर करने के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, ताकि राजस्थान बोवाइन एनिमल (वध पर रोक और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 (जिसे इसके बाद “राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995” या “आरबीए एक्ट, 1995” कहा गया है) की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा पारित चार अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी जा सके। ये आदेश जब्त किए गए परिवहन के साधनों (वाहनों) की जब्ती, रिहाई या रिहाई से इनकार करने से संबंधित हैं, जिन्हें पुलिस ने राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संबंधित एफआईआर दर्ज करते समय जब्त किया था, इस आधार पर कि प्रश्नगत वाहनों का कथित तौर पर आरबीए एक्ट, 1995 के तहत एक अपराध करने में उपयोग किया गया था।

2. चूंकि इन सभी याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना है कि उनके संबंधित वाहनों (परिवहन के साधनों) को सुपुर्दगी या अंतरिम हिरासत पर छोड़ा जाए, और फलस्वरूप संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा आरबीए एक्ट, 1995 के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में पारित किए गए दोषपूर्ण आदेशों को रद्द किया जाए, इसलिए यह वांछनीय है कि राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 के तहत किसी अपराध के संबंध में जब्त किए गए वाहन को छोड़ने या जब्त करने के लिए जिला कलेक्टर की शक्ति और अधिकार क्षेत्र के दायरे पर विचार किया जाए।

3. इस संबंध में, मूल राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 में, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के संबंध में उपयोग किए जाने वाले “परिवहन के साधनों” की जब्ती और अधिग्रहण के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, जब इस कमी को राज्य विधायिका के ध्यान में लाया गया और यह प्रस्तावित किया गया कि राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 में निहित प्रावधानों के समान, परिवहन के साधनों की जब्ती और अधिग्रहण के लिए प्रावधान को आरबीए एक्ट, 1995 में सम्मिलित करना आवश्यक है, तो राज्य विधायिका ने 05.12.2019 से प्रभावी राजस्थान बोवाइन एनिमल (वध पर रोक और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लागू करके आरबीए एक्ट, 1995 में धारा 6-ए जोड़ी। बोवाइन पशु की जब्ती और निपटान का प्रावधान मूल आरबीए एक्ट में धारा 7 के तहत उपलब्ध था। तत्काल संदर्भ के लिए, राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की नव-सम्मिलित धारा 6-ए और पहले से मौजूद धारा 7 के प्रावधान को यहाँ नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:-

“6-ए. परिवहन के साधन का अधिग्रहण।- (1) जब भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसे अपराध को करने में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के किसी भी साधन को जब्त किया जाएगा।

(2) जहां उप-धारा (1) में संदर्भित परिवहन के किसी भी साधन को इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को करने के संबंध में जब्त किया जाता है, तो ऐसी जब्ती की रिपोर्ट, बिना किसी अनुचित देरी के, इसे जब्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी

को दी जाएगी। और चाहे ऐसे अपराध को करने के लिए कोई मुकदमा चलाया गया हो या नहीं, सक्षम प्राधिकारी, जिसके पास उस क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है जहां उक्त परिवहन के साधन को जब्त किया गया था, यदि वह संतुष्ट है कि उक्त परिवहन के साधन का उपयोग इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया गया था, तो वह उक्त परिवहन के साधन के अधिग्रहण का आदेश दे सकता है।

बशर्ते कि उक्त परिवहन के साधन के अधिग्रहण का आदेश देने से पहले, उक्त परिवहन के साधन के मालिक को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाएगा और यदि ऐसा मालिक सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या होने की संभावना थी और उसने ऐसे अपराध को होने से रोकने में उचित सावधानी बरती थी, तो सक्षम प्राधिकारी उक्त परिवहन के साधन को जब्त नहीं कर सकता है।

बशर्ते कि जहां ऐसा परिवहन का साधन केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी उपक्रम के स्वामित्व में है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे परिवहन के साधन के अधिग्रहण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले को राज्य सरकार को ऐसे आदेश देने के लिए संदर्भित किया जाएगा जो राज्य सरकार परिवहन के साधन के संबंध में उचित समझे।

यह भी बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत अधिग्रहण का आदेश देने से पहले, उप-धारा (1) में संदर्भित परिवहन के साधन के मालिक को अधिग्रहण के बदले में, ऐसे परिवहन के साधन के बाजार मूल्य से अधिक नहीं का जुर्माना देने का विकल्प दिया जा सकता है।

यह भी बशर्ते कि परिवहन के साधन के मालिक को पिछले परंतुक के तहत विकल्प नहीं दिया जाएगा, यदि उसे पहले किसी अवसर पर उस परंतुक के तहत विकल्प दिया गया था।

(3) जब भी इस अधिनियम के तहत अपराध करने के संबंध में उप-धारा (1) में संदर्भित परिवहन के किसी भी साधन को जब्त किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास, और उस समय लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के पास, ऐसे परिवहन के साधन के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई के संबंध में आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि यह जनहित में या उसके मालिक के लाभ के लिए समीचीन है कि इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए जब्त किए गए परिवहन के साधन, जैसा कि उप-धारा (1) में संदर्भित है, को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाए, तो वह किसी भी समय इसे बेचने का निर्देश दे सकता है।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया अधिग्रहण का कोई भी आदेश किसी भी दंड को लागू होने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी है।”

7. जब्त किए गए बोवाइन पशु की हिरासत और निपटान।

(1) जब भी खोज या जब्ती के परिणामस्वरूप या निरीक्षण या अन्यथा के परिणामस्वरूप बोवाइन पशुओं को जब्त किया जाता है, तो मामले के अंतिम निपटान तक जब्त किए गए बोवाइन पशुओं की हिरासत को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा ऐसे जानवरों के कल्याण

के लिए काम करने वाली किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसी को या राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम 24 of 1960) के प्रावधानों के तहत शासित गौशाला या गोसदन को सौंपा जा सकता है।

बशर्ते कि जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसी कोई स्वैच्छिक एजेंसी या गौशाला या गोसदन नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी बोवाइन पशुओं की हिरासत को क्षेत्र के बाहर किसी भी ऐसी एजेंसी, गौशाला या गोसदन को या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकता है, जो ऐसे जानवर को बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से काम करता है।

(2) जब भी किसी मामले का अंतिम निपटान होता है, तो बोवाइन पशु की हिरासत या स्थायी सौंपने के संबंध में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधों के अधीन किए जाएंगे जो उचित समझे जा सकते हैं।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उक्त आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, संभागीय आयुक्त को इसके खिलाफ अपील कर सकता है।

(4) ऐसी अपील पर संभागीय आयुक्त अपीलकर्ता और सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील के निपटारे तक आदेश को रोके जाने का निर्देश दे सकता है या आदेश को संशोधित, बदल या रद्द कर सकता है और कोई भी आगे के आदेश दे सकता है जो न्यायसंगत हो।

(5) जब भी इस अधिनियम के तहत किसी भी बोवाइन पशु को जब्त किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी या संभागीय आयुक्त के पास, और उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, किसी भी अन्य न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के पास ऐसे जानवर के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई के संबंध में आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।”

4. राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित धारा 6-ए के प्रावधान के सीधे अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध को करने में उपयोग किए गए किसी भी परिवहन के साधन को जब्त किया जा सकता है। इसके तहत, जब्ती का आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र केवल "सक्षम प्राधिकारी" को सौंपा गया है, जिसके पास उस क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र है जहां उक्त परिवहन के साधन को जब्त किया गया था। “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ संबंधित जिले का कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी है, जिसे आरबीए एक्ट, 1995 की धारा 2(जी) के तहत परिभाषित किया गया है। नव-सम्मिलित धारा 6-ए में यह निर्धारित किया गया है कि उक्त परिवहन के साधन की जब्ती का आदेश पारित किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि उक्त परिवहन के साधन का उपयोग इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया गया था। धारा 6-ए से जुड़े परंतुक में यह भी परिकल्पित है कि परिवहन के साधन के अधिग्रहण का आदेश पारित करने से पहले, उक्त परिवहन के साधन के मालिक को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाएगा और उसे इसके

अधिग्रहण के बदले में, ऐसे परिवहन के साधन के बाजार मूल्य से अधिक नहीं का जुर्माना देने का विकल्प दिया जा सकता है। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 6-ए के तहत परिवहन के साधन के अधिग्रहण की कार्यवाही से निपटते समय, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी की तरह कार्य करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की उप-धारा (3) की धारा 6-ए के आधार पर, “सक्षम प्राधिकारी” को इस अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में जब्त किए गए ऐसे परिवहन के साधन के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई के संबंध में आदेश देने के लिए भी अधिकृत किया गया है, और उस समय लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। अधिनियम की धारा 7, आरबीए एक्ट, 1995 के तहत जब्त किए गए बोवाइन पशु की हिरासत और निपटान से निपटने के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है।

5. राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 एक विशेष अधिनियम है, जिसे राज्य विधायिका द्वारा गाय और उसके वंश के वध को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ राजस्थान राज्य से अन्य राज्यों में उनके अस्थायी प्रवासन या निर्यात को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। आरबीए एक्ट, 1995 की धारा 2 विभिन्न शब्दों की परिभाषा प्रदान करती है। धारा 3 से 6 और 8 से 10 में, विभिन्न प्रकार के अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 6-ए “परिवहन के साधनों” की जबती और अधिग्रहण से संबंधित है और धारा 7 “बोवाइन पशु” की हिरासत और निपटान को नियंत्रित करती है, जिसे इस अधिनियम के तहत जब्त किया गया है। धारा 11 यह प्रावधान करती है कि आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाए गए व्यक्ति पर यह

साबित करने का भार होगा कि उसने ऐसे अपराध नहीं किए थे। धारा 12 सक्षम प्राधिकारी को उन स्थानों में प्रवेश करने, निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करती है, जहां भी सक्षम प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध किए गए हैं या किए जाने की संभावना है। धारा 12-ए के तहत, सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या गिरफ्तार करने का कारण बनने का भी अधिकार दिया गया है, जो उसकी उपस्थिति में, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करता है, साथ ही सक्षम प्राधिकारी को किसी भी परिवहन के साधन को जब्त करने या जब्त करने का कारण बनने का भी अधिकार दिया गया है जिसका उपयोग इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने में किया जा रहा है।

6. यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि यह विशेष अधिनियम यानी आरबीए एक्ट, 1995, गाय और उसके वंश के वध को रोकने और उन्हें चोट न पहुँचाने के साथ-साथ राजस्थान राज्य से बोवाइन पशु के अस्थायी प्रवासन या निर्यात को विनियमित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों को शामिल करता है, जैसा कि इस अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों के लिए दंड के लिए है, लेकिन यह अधिनियम कहीं भी आरबीए एक्ट, 1995 के तहत दंडनीय अपराधों की प्रकृति को निर्दिष्ट नहीं करता है, कि क्या ऐसे अपराध संज्ञेय हैं या गैर-संज्ञेय हैं? और न ही ऐसे अपराधों की जांच, पूछताछ और परीक्षण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऐसी आकस्मिकताओं में, सीआरपीसी की धारा 4(2) के आधार पर, आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जांच, पूछताछ, परीक्षण और अन्यथा से निपटने के लिए उत्तरदायी हैं और संज्ञेय के रूप में माने जाते हैं। इसलिए, एक पुलिस अधिकारी को एक एफआईआर

दर्ज करने और जांच के लिए आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें गलत काम करने वाले को गिरफ्तार करने की उसकी शक्ति का प्रयोग करना भी शामिल है, साथ ही बोवाइन पशु और परिवहन के साधन को जब्त करना भी शामिल है, जिसका उपयोग ऐसे अपराध को करने में किया जाता है। अधिनियम की धारा 12 और 12-ए के तहत, सक्षम प्राधिकारी को भी उन स्थानों में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति और क्षेत्राधिकार दिया गया है, साथ ही गलत काम करने वाले को गिरफ्तार करने और किसी भी परिवहन के साधन को जब्त करने के लिए भी अधिकृत किया गया है, जिसका उपयोग अधिनियम के तहत बोवाइन पशु के साथ अपराध करने में किया जाता है।

7. दोहराव के जोखिम पर, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आरबीए एक्ट, 1995 में नव-सम्मिलित धारा 6-ए, विशेष रूप से यह निर्धारित करती है कि आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध(अपराधों) को करने में उपयोग किए गए परिवहन के साधन के अधिग्रहण की शक्ति और अधिकार क्षेत्र केवल सक्षम प्राधिकारी को निहित होगा और धारा 6-ए की उप-धारा (3) में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि जब भी इस अधिनियम के तहत अपराध को करने के संबंध में परिवहन के किसी भी साधन को जब्त किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास, और उस समय लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के पास, ऐसे परिवहन के साधन के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई के संबंध में आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। धारा 6-ए की उप-धारा (5) यह स्पष्ट करती है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया अधिग्रहण का कोई भी आदेश किसी भी दंड को लागू होने से नहीं रोकेगा जिसके लिए प्रभावित व्यक्ति आरबीए एक्ट, 1995

के तहत उत्तरदायी है। इस प्रकार, विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी का ऐसा अधिकार क्षेत्र स्वतंत्र, विशिष्ट और अलग है, चाहे गलत काम करने वाले के खिलाफ अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया हो या नहीं।

8. यह देखा गया है कि आरबीए एक्ट, 1995 की धारा 7 बोवाइन पशु की जब्ती, हिरासत और निपटान से संबंधित है, जो सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाता है। धारा 7 की उप-धारा (5) आगे यह स्पष्ट करती है कि जब भी इस अधिनियम के तहत किसी भी बोवाइन पशु को जब्त किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी या संभागीय आयुक्त के पास होगा, और उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, किसी भी अन्य न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के पास ऐसे जानवर के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई के संबंध में आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इस प्रकार, अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिले का कलेक्टर एक ही प्राधिकारी है, जिसे बोवाइन पशु की हिरासत और निपटान के मुद्दे से निपटने के लिए अधिकृत और सौंपा गया है, साथ ही आरबीए एक्ट, 1995 के तहत जब्त किए गए परिवहन के साधन के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई और अधिग्रहण से निपटने के लिए भी अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार को अधिनियम में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

9. ऊपर संदर्भित प्रावधानों और गाय और उसके वंश के वध की रोकथाम से निपटने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के मद्देनजर और किसी भी बोवाइन पशु को चोट से बचाने के लिए, साथ ही राजस्थान राज्य से अस्थायी या स्थायी प्रवासन को विनियमित करने के लिए, यह सुरक्षित रूप

से माना जा सकता है और देखा जा सकता है कि बोवाइन पशु के साथ-साथ परिवहन के साधन को भी, आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध (अपराधों) के संबंध में पुलिस या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है, लेकिन आरबीए एक्ट, 1995 में उपलब्ध धारा 7 और 6-ए के विशेष प्रावधानों के आधार पर, बोवाइन पशु के कब्जे, वितरण और निपटान या रिहाई के विषय वस्तु से निपटने के लिए और परिवहन के साधन के कब्जे, वितरण, निपटान, रिहाई और अधिग्रहण के संबंध में, विशेष क्षेत्राधिकार सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिले के कलेक्टर को दिया गया है और किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है। इसलिए, "परिवहन के साधन" के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई और अधिग्रहण के संबंध में जिसके बारे में यह न्यायालय वर्तमान याचिकाओं में चिंतित है, विशेष अधिनियम, आरबीए एक्ट, 1995, की सांविधिक प्रावधान, धारा 6-ए, सीआरपीसी के सामान्य कानून के प्रावधानों पर प्रबल होगा और उसे रद्द कर देगा। इसे धारण करने के लिए, सीआरपीसी की धारा 5 को सेवा में दबाया जा सकता है और मैक्सिम *generalia specialibus non derogant* (विशिष्ट नियम, सामान्य नियमों पर हावी होते हैं) संचालन में आता है। इस संबंध में कानून का प्रस्ताव अच्छी तरह से तय है कि विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रबल होगा। सुरेश नंदा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [(2008) 3 SCC 674] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी, इस मुद्दे पर न्यायिक मिसालों का पालन करते हुए, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न पिछले निर्णयों में तय किया गया है, पर्याप्त होगी, जिसमें पैरा नंबर 10 में, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित और देखा गया था कि "जहां एक विशेष अधिनियम विशिष्ट विषय से निपट रहा है, वहां सामान्य अधिनियम

के बजाय उस अधिनियम का सहारा लेना चाहिए जो विशिष्ट अधिनियम से संबंधित मामले के लिए प्रदान करता है।”

यह आगे यहां आयोजित और देखा गया है कि चूंकि आरबीए एक्ट, 1995 कहीं भी अपराधों की प्रकृति और अधिनियम के तहत दंडनीय ऐसे अपराधों की जांच और परीक्षण के लिए प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए, उस संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के सामान्य कानून के प्रावधान, सीआरपीसी की धारा 4(2) के आधार पर लागू होंगे। कानून का यह सुप्रसिद्ध प्रस्ताव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम विमल कुमार सुराना [(2011) 1 SCC 534]** के मामले में दिए गए निर्णय के पैरा नंबर 41 में नोट किया गया था। इसलिए, आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जांच, पूछताछ, परीक्षण और अन्यथा से निपटने के लिए उत्तरदायी हैं।

10. जैसा कि यहां ऊपर नोट किया गया है, सीआरपीसी की धारा 4(2) के आधार पर, आरबीए एक्ट, 1995 के तहत दंडनीय अपराधों को प्रकृति में संज्ञेय माना जाता है और एक पुलिस अधिकारी को आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध(अपराधों) को करने के संबंध में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत किया जाता है, साथ ही उस स्थान में प्रवेश करने, निरीक्षण करने की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का भी अधिकार होता है, जहां भी यह माना जाता है या यह मानने का कारण होता है कि आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध किए गए हैं या किए जाने की संभावना है। इस संबंध में, यह भी विवादित नहीं हो सकता है कि पुलिस अधिकारी भी आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध करने के संबंध में उपयोग किए गए

बोवाइन पशु और परिवहन के साधन की खोज और जब्ती की शक्तियों और अधिकार का भी अधिकार रखता है, सिवाय इसके कि गलत काम करने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति का भी अधिकार होता है। लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा बोवाइन पशु और परिवहन के साधन की जब्ती के बाद, यह केवल सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अधिकृत अन्य अधिकारी है, जो जब्त किए गए बोवाइन पशु के वितरण, निपटान के लिए और जब्त किए गए ऐसे परिवहन के साधन के कब्जे, वितरण और निपटान या रिहाई से निपटने के लिए या ऐसे परिवहन के साधन को जब्त करने के लिए शक्ति और क्षेत्राधिकार रखता है। इस संबंध में, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार को आरबीए एक्ट, 1995 के तहत विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

11. पूरे आरबीए एक्ट, 1995 के प्रावधानों के अवलोकन से, जो परिलक्षित हुआ है, वह यह है कि, एक पुलिस अधिकारी के अलावा, सक्षम प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी भी, अधिनियम की धारा 12 के तहत, उस स्थान में प्रवेश करने और निरीक्षण करने के लिए सशक्त है, जहां उसके पास यह मानने का कारण है कि आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध किए गए हैं या किए जाने की संभावना है और धारा 12-ए के तहत, वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या गिरफ्तार करने का कारण बनने के लिए भी सशक्त है, जो उसकी उपस्थिति में, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करता है, जैसा कि परिवहन के साधन और बोवाइन पशुओं को जब्त करने या जब्त करने का कारण बनने का भी अधिकार क्षेत्र है। लेकिन, अधिनियम में, केवल सक्षम प्राधिकारी को ही जब्त किए गए बोवाइन पशुओं के वितरण और निपटान से निपटने के लिए अधिकृत किया गया है,

जैसा कि जब्त किए गए ऐसे परिवहन के साधन के वितरण, निपटान या रिहाई या अधिग्रहण से निपटने के लिए भी अधिकृत किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि स्थान में प्रवेश करने और निरीक्षण करने और अपराधी, बोवाइन पशु और परिवहन के साधन को गिरफ्तार करने और जब्त करने की शक्ति का प्रयोग एक पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध(अपराधों) के संबंध में एक आपराधिक मामला (एफआईआर) दर्ज किया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं में, जब्त के बाद, बोवाइन पशु की हिरासत, वितरण और निपटान के साथ-साथ ऐसे परिवहन के साधन के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई या अधिग्रहण से निपटने का विषय, केवल आरबीए एक्ट, 1995 के तहत परिभाषित सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, और किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार को इस संबंध में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

12. हाथ में वर्तमान चार याचिकाओं के विचित्र तथ्यों पर आते हैं, याचिकाकर्ताओं का संबंधित मामला यह है कि उनके वाहनों को आरबीए एक्ट, 1995 के तहत अपराध(अपराधों) को करने के लिए एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस द्वारा जब्त किया गया था और उसके बाद, सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिला कलेक्टर ने आरबीए एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत उसे सौंपे गए अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दोषपूर्ण आदेश पारित किए हैं। विवरण से रहित, प्रत्येक मामले के संक्षेप में तथ्य, इस प्रकार हैं:

13. एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2097/2024 में, दिनांक 05.07.2023 के आदेश के माध्यम से, जिला कलेक्टर, झालावाड़ ने

पुलिस स्टेशन भवानी मंडी, झालावाड़ में दर्ज एफआईआर संख्या 125/2023 के संबंध में जब्त किए गए वाहन यानी पिक-अप महिंद्रा पंजीकरण संख्या आरजे-20-जीबी-8328 को जब्त करने का आदेश पारित किया है, यह मानते हुए कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग बिना परमिट के बोवाइन पशुओं को परिवहन करने के लिए किया गया था, इसलिए यह स्थापित है कि वाहन का उपयोग राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 5, 6, 8, 9 और 11 के तहत अपराध करने में किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाहन के मालिक यानी वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर छोड़ने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, प्रश्नगत वाहन के अधिग्रहण के बदले में, याचिकाकर्ता को बीमा के दस्तावेज में इंगित ऐसे वाहन के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना राशि का भुगतान/जमा करने का विकल्प दिया गया है और यदि याचिकाकर्ता बाजार मूल्य के बराबर ऐसी राशि जमा करता है, तो वाहन को याचिकाकर्ता को सुपुर्दगी पर छोड़ दिया जाए, अन्यथा वाहन को कानून के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाए। जुर्माना राशि 4 लाख रुपये की राशि तक निर्धारित की गई थी, लेकिन दिनांक 03.10.2023 के शुद्धिपत्र आदेश के माध्यम से बीमा के दस्तावेज में इंगित 3,50,000/- रुपये की राशि तक इसे ठीक और कम कर दिया गया है।

14. एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1978/2024 में, जिला कलेक्टर, झालावाड़ द्वारा पारित दिनांक 20.02.2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत, परिवहन के साधन (वाहन) पंजीकरण संख्या एमपी-43-जी-5257 को, जिसे पुलिस द्वारा 21.05.2023 को पुलिस स्टेशन भवानी मंडी, झालावाड़ में राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 5, 6, 8, 9 और 11 के तहत अपराधों के लिए दर्ज

एफआईआर संख्या 207/2023 के संबंध में जब्त किया गया था, को कलेक्टर द्वारा राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जब्त करने का आदेश दिया गया है और उसी आदेश से, पंजीकृत मालिक को बीमा के दस्तावेज में इंगित वाहन के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना राशि जमा करने का विकल्प दिया गया है और ऐसी जुर्माना राशि जमा करने पर, वाहन को सुपुर्दगी पर पंजीकृत मालिक को छोड़ने की अनुमति दी गई है, अन्यथा वाहन को जब्त करने के लिए आयोजित किया गया है।

15. एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6030/2023 में, आदेश दिनांक 03.08.2023 का है जो जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पारित किया गया है, जिसके द्वारा और जिसके तहत, वाहन- पिक-अप पंजीकरण संख्या यूपी-85-सीटी-1695, जिसे पुलिस द्वारा पी.एस. डीग, भरतपुर में राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 5 और 8 के तहत अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 257/2022 के संबंध में जब्त किया गया था, को जब्त करने का आदेश दिया गया है और अधिग्रहण के बदले में, याचिकाकर्ता को वाहन को छोड़ने के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का विकल्प दिया गया है। दोषपूर्ण आदेश के अवलोकन से, यह पता चलता है कि प्रश्नगत वाहन को पुलिस द्वारा रोका गया था और खोज पर, यह पाया गया कि वाहन में बोवाइन पशुओं (चार गायों) को बिना किसी परमिट के परिवहन किया जा रहा था, इसलिए, वाहन को जब्त कर लिया गया था और ऊपर बताए गए अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।

16. एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1941/2024 में, दिनांक 20.03.2024 को जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को प्रश्नगत वाहन को सुपुर्दगी पर छोड़ने के लिए खारिज कर दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत वाहन को पुलिस द्वारा रोका गया था और खोज पर, यह पाया गया कि बोवाइन पशुओं को परिवहन के लिए बिना किसी लाइसेंस या परमिट के वाहन में परिवहन किया जा रहा था, इसलिए, पुलिस ने पुलिस स्टेशन जवाजा, ब्यावर में राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 5, 6 और 8 के तहत अपराधों के लिए एक एफआईआर संख्या 408/2023 दर्ज की, और प्रश्नगत वाहन, एक ट्रक पंजीकरण संख्या एमएच-20-ईएल-9524 को जब्त कर लिया।

याचिकाकर्ता ने, खुद को प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत मालिक बताते हुए, वाहन को सुपुर्दगी पर छोड़ने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन उसके आवेदन को जिला कलेक्टर द्वारा दोषपूर्ण आदेश के माध्यम से इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया है कि राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की संशोधित धारा 6-ए के अनुसार वाहन को जब्त किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी ने दोषपूर्ण आदेश में प्रश्नगत वाहन की जब्ती के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है।

17. संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा, सक्षम प्राधिकारी होने की क्षमता में, आरबीए एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित दोषपूर्ण आदेशों के गुण-दोषों में जाने से पहले और

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषपूर्ण आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के jurisdictional मुद्दे में प्रवेश करने से पहले, इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से और उनकी ओर से पेश होने वाले वकीलों से एक प्रश्न रखा, कि क्या आरबीए एक्ट, 1995 के तहत पीड़ित व्यक्ति को जिला कलेक्टर यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 6-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए कोई सांविधिक अपील या पुनरीक्षण का उपाय प्रदान किया गया है, या तो संभागीय आयुक्त के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष?

18. इस न्यायालय द्वारा उठाया गया प्रश्न निश्चित रूप से अत्यधिक महत्व का है और इसे पहले संबोधित करने की आवश्यकता है, इसलिए, यह न्यायालय पहले उदाहरण में, सामान्य महत्व के ऐसे कानूनी प्रश्न से निपटना उचित और उचित समझता है। चूंकि उपरोक्त कानूनी प्रश्न सामान्य महत्व का है, जो इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया, इसलिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से और उनकी ओर से पेश होने वाले वकीलों के अलावा, बार के अन्य विद्वान सदस्यों को भी, अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के इस कानूनी मुद्दे का जवाब देने के लिए, न्याय मित्र के रूप में न्यायालय को अपनी मूल्यवान सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

19(i). कानून के उपरोक्त प्रश्न के संबंध में, अपील या पुनरीक्षण के किसी भी वैकल्पिक सांविधिक उपाय की उपलब्धता के बारे में, जिला कलेक्टर द्वारा आरबीए एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्ति

और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित दोषपूर्ण आदेशों के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह बताया गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा धारा 6-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण दायर करने का कोई विशिष्ट उपाय आरबीए एक्ट, 1995 में प्रदान नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि यद्यपि जिला कलेक्टर यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरबीए एक्ट, 1995 की धारा 7(1) या 7(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के खिलाफ, जब्त किए गए बोवाइन पशु की हिरासत, वितरण और निपटान के संबंध में, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, कोई भी व्यथित व्यक्ति, धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अनुसार संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा, अधिनियम की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जब्त किए गए परिवहन के साधनों के वितरण या रिहाई या अधिग्रहण के संबंध में पारित आदेश के खिलाफ ऐसी कोई सांविधिक अपील प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, ऐसी आकस्मिकता में, याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं, ताकि जिला कलेक्टर द्वारा पारित दोषपूर्ण आदेशों को चुनौती दी जा सके, उनके वाहनों को सुपुर्दगी पर या अंतरिम हिरासत में छोड़ने से इनकार करते हुए और उनके वाहनों यानी आरबीए एक्ट, 1995 के तहत जब्त किए गए परिवहन के साधनों के अधिग्रहण का निर्देश देते हुए, हालांकि एफआईआर से उत्पन्न आपराधिक मामला, जिसमें उनके वाहन को जब्त किया गया है, अभी तक अंतिम रूप से समाप्त नहीं हुआ है और आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है।

19(ii). एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2097/2024 में पेश याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, जो दिनांक 05.07.2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें पुलिस थाना भवानी मंडी, झालावाड़ में दर्ज एफआईआर संख्या 125/2023 के संबंध में जब्त किए गए वाहन यानी पिक-अप महिंद्रा जिसका पंजीकरण संख्या आरजे-20-जीबी-8328 है, को जब्त कर लिया गया था, ने बताया है कि उसी एफआईआर संख्या 125/2023 में जो पुलिस थाना भवानी मंडी, झालावाड़ में आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 5, 6, 8, 9 और 11 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11, 11(1)(डी), 11(1)(के), 11(1)(एल) और 11(1)(एम) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी, एक अन्य वाहन यानी बोलेरो जिसका पंजीकरण संख्या आरजे-01-जीबी-2617 है और जो पंजीकृत मालिक श्री पप्पू से संबंधित है, को भी जब्त किया गया था। यह बताया गया है कि जिला कलेक्टर ने दिनांक 05.07.2023 के एक अलग आदेश के माध्यम से वाहन संख्या आरजे-01-जीबी-2617 को जब्त करने का निर्देश दिया था, यह मानते हुए कि इसका उपयोग आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध करने में किया गया था, और अधिग्रहण के बदले में, 4 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था, जिससे वाहन को सुपुर्दगी पर छोड़ने की अनुमति मिली। यह आदेश जिला कलेक्टर द्वारा आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, जिसके खिलाफ पंजीकृत मालिक श्री पप्पू ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7340/2023; पप्पू बनाम राजस्थान राज्य दायर की थी। उस याचिका में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 02.02.2024 के आदेश के

माध्यम से वाहन-बोलेरो जिसका पंजीकरण संख्या आरजे-01-जीबी-2617 है, को इसके पंजीकृत मालिक को 1 लाख रुपये की बैंक गारंटी और इतनी ही राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर अंतरिम हिरासत पर छोड़ने का निर्देश दिया था, साथ ही आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान वाहन को हस्तांतरित न करने की शर्त भी याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाई गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता ने इसी एफआईआर संख्या 125/2023 से उत्पन्न वर्तमान याचिका में भी इसी तरह की राहत की प्रार्थना की है।

19(iii). एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7340/2023 में इस उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 02.02.2024 के आदेश के अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि समन्वय पीठ ने उच्च न्यायालय के एक अन्य पिछले आदेश दिनांक 08.09.2022 पर भरोसा किया था जो एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6641/2022; रशीद बनाम राजस्थान राज्य में पारित किया गया था, जिसमें कोई अधिग्रहण कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी और उच्च न्यायालय ने आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत जब्त किए गए वाहन को 3 लाख रुपये की बैंक गारंटी पेश करने पर अंतरिम हिरासत पर छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ एसएलपी (आपराधिक) संख्या 9311/2022 दायर की गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंक गारंटी की राशि को घटाकर केवल 1 लाख रुपये कर दिया गया था। इसलिए, समन्वय पीठ ने दिनांक 02.02.2024 का आदेश पारित किया और उसी तर्क को लागू करते हुए वाहन को छोड़ दिया।

19(iv). लेकिन यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि याचिका संख्या 7340/2023 में पारित दिनांक 02.02.2024 के आदेश में या याचिका

संख्या 6641/2022 में पारित दिनांक 08.09.2022 के आदेश में या इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश में, कानून के दोनों मुद्दों:-

(I) आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत शक्तियों के प्रयोग में पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण के किसी भी वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता से संबंधित; और,

(II) सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रयोग में उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से संबंधित मुद्दे,

न तो उठाए गए थे और न ही समन्वय पीठ ने ऐसे मुद्दों से निपटा था, न ही राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी अन्य आदेश को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, जो यहां ऊपर संदर्भित दोनों मुद्दों से निपटता हो।

19(v). इसलिए, इस न्यायालय की अन्य आपराधिक विविध याचिकाओं में पारित समन्वय पीठों के आदेश कानूनी मुद्दों को तय करने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं, जिन पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है और संबोधित किया जा रहा है।

20(i). न्याय मित्र के रूप में पेश होने की अनुमति दिए गए बार के विद्वान सदस्यों की ओर से, यह आग्रह किया गया है कि नव-सम्मिलित धारा 6-ए के प्रावधान से कहीं भी यह परिलक्षित नहीं होता है कि राज्य विधायिका का इरादा धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अधिग्रहण के आदेश को कोई अंतिम रूप देना था और इसके

खिलाफ अपील या पुनरीक्षण का कोई उपाय प्रदान नहीं करना था। यह आग्रह किया गया है कि धारा 6-ए के पूरे प्रावधान में, यह कहीं भी निर्धारित नहीं है कि इस धारा के तहत शक्ति के प्रयोग के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम और निर्णायक होगा जैसा कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 5(8) के तहत संभागीय आयुक्त के आदेश के संबंध में उल्लेख किया गया है।

20(ii). यह भी आग्रह किया गया है कि मूल आरबीए अधिनियम, 1995 में, बोवाइन पशु को जब्त करने की शक्तियां उपलब्ध थीं और सक्षम प्राधिकारी पहले से ही जब्त किए गए बोवाइन पशु की हिरासत, वितरण और निपटान से निपटने के लिए अधिकृत था, जैसा कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत परिकल्पित है, लेकिन आरबीए अधिनियम में, परिवहन के साधन की जब्त और अधिग्रहण के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिसका उपयोग इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के संबंध में किया जाता है, इसलिए, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 में निहित प्रावधानों के अनुरूप, धारा 6-ए का प्रावधान राज्य विधायिका द्वारा 05.12.2019 के संशोधन, 2018 को पेश करके सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार, धारा 6-ए के संशोधित प्रावधान के आधार पर, राज्य विधायिका का इरादा सक्षम प्राधिकारी को आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध करने के संबंध में जब्त किए गए परिवहन के साधनों के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई या अधिग्रहण से निपटने के लिए शक्ति और क्षेत्राधिकार सौंपना था। जब राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित परिवहन के साधन के अधिग्रहण के आदेश के खिलाफ, धारा 9-ए के आधार पर कानून में अपील का उपाय प्रदान किया जाता है और आरबीए अधिनियम, 1995

में भी, कलेक्टर द्वारा बोवाइन पशु के वितरण और निपटान के संबंध में धारा 7(1) या (2) के तहत पारित आदेश के खिलाफ, संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील का उपाय धारा 7(3) के तहत निर्धारित किया गया है, यह राज्य विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है कि कलेक्टर द्वारा धारा 6-ए के तहत परिवहन के साधन के वितरण, निपटान या रिहाई या अधिग्रहण के संबंध में पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति को आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपील के उपाय से वंचित किया जाए। इसलिए, जिला कलेक्टर यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 6-ए के तहत पारित आदेश को भी अपील द्वारा चुनौती देने योग्य और संभागीय आयुक्त के समक्ष चुनौती देने योग्य माना जाना चाहिए, उसी तरह जिस तरह कलेक्टर यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के तहत पारित आदेश के खिलाफ आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रदान की जाती है।

20(iii). इसलिए, ऊपर संदर्भित तर्क के आधार पर, न्याय मित्र के रूप में पेश होने वाले बार के विद्वान सदस्यों के एक समूह का तर्क यह है कि संभागीय आयुक्त के समक्ष धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील के उपाय की उपलब्धता को या तो "निहित शक्ति के सिद्धांत" को लागू करके या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या और धारा 6-ए और धारा 7 दोनों के प्रावधानों को संचयी प्रभाव देकर, और "कैसस ओमिशनस के सिद्धांत" को लागू करके एक तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए माना जाना चाहिए।

20(iv). ऐसे तर्कों को पुष्ट करने के लिए, **साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2008) 2 SCC 409]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के

निर्णय का संदर्भ दिया गया है, यह तर्क देने के लिए कि निहित शक्ति के सिद्धांत के नियम को संभागीय आयुक्त को धारा 6-ए के तहत भी पारित जिला कलेक्टर यानी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र मानने और सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा सकता है और **परमजीत कुमार सरोया बनाम भारत संघ [AIR 2014 P&H 121]** के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, यह तर्क देने के लिए कि यह केवल एक आकस्मिक चूक का मामला है न कि राज्य विधायिका की ओर से जानबूझकर बहिष्करण का, कि धारा 6-ए के प्रावधान में अपील के उपाय को निर्धारित करने वाले किसी भी विशिष्ट शब्दों को प्रदान नहीं किया गया है, और ऐसे लापता शब्दों को प्रभावी प्रासंगिक अर्थ देने और विधायिका के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 7(3) और समान प्रकृति के अन्य कानून में निर्धारित है, इसलिए, इस विसंगति से बचने का एकमात्र तरीका उद्देश्यपूर्ण व्याख्या और *कैसस ओमिशस* (चूक का मामला) दोनों के सिद्धांतों को सेवा में लाना है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 6-ए के तहत पारित आदेश के खिलाफ, संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील के उपाय को कानून में उपलब्ध माना जाना चाहिए।

21. एक और तर्क, पूरी ताकत और अनुनय के साथ दिया गया है, कि यह कानून का एक अच्छी तरह से तय प्रस्ताव है कि अपील का अधिकार एक प्राकृतिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है। अपील का अधिकार तब तक मौजूद नहीं माना जा सकता जब तक कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो। अपील का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है और यह केवल तभी उपलब्ध है जब इसे कानून द्वारा प्रदान किया गया हो, और

अपील का उपाय, कानून की एक रचना होने के नाते, केवल तभी उपलब्ध होता है जब इसे सांविधिक प्रावधान में निर्धारित किया जाता है। चूंकि धारा 6-ए के प्रावधान में, संभागीय आयुक्त के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए व्यथित व्यक्ति इसके खिलाफ अपील के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता है। यह प्रचारित किया गया है कि कानून का ऐसा प्रस्ताव अच्छी तरह से ज्ञात और तय है, जिसके लिए **मैसर्स सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2009) 10 SCC 531]** और **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दिलबहार सिंह [(2014) 9 SCC 102]** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का संदर्भ पर्याप्त होगा।

22. इस न्यायालय को अवगत कराया गया है कि मूल अधिनियम में धारा 6-ए का प्रावधान, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 के तहत निहित प्रावधानों के समान ही सम्मिलित किया गया था। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69, उन चीजों के बारे में बात करती है जो अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। इस धारा में, उप-धारा (1) में क्लॉज़ (ई) परिवहन के अधिग्रहण के लिए और साथ ही उप-धारा (4) को राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से दिनांक 03.05.2000 से प्रभावी रूप से सम्मिलित किया गया था। धारा 69 की उप-धारा (5) में, उप-धारा (4) के तहत किए गए अधिग्रहण के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को अपील का उपाय प्रदान किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि आबकारी विभाग के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील और पुनरीक्षण का उपाय, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9-ए के तहत विशेष रूप से निर्धारित

किया गया है, इसलिए, बाद में, धारा 69 की उप-धारा (5) को दिनांक 24.05.2005 से प्रभावी रूप से हटा दिया गया था और संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा सम्मिलित किए जाने पर ऐसी धारा आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए में जगह नहीं पा सकी। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में, आबकारी अधिनियम के तहत अपराध करने के संबंध में जब्त किए गए परिवहन के साधन के अधिग्रहण की शक्तियां, आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पद से नीचे के अधिकारी को सौंपी गई हैं, जैसा कि धारा 69 की उप-धारा (4) के तहत प्रदान किया गया है, और उसके खिलाफ, अपील और पुनरीक्षण का सांविधिक उपाय धारा 9-ए के आधार पर निर्धारित किया गया है, लेकिन जिला कलेक्टर यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 6-ए के तहत पारित अधिग्रहण के आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण दायर करने का उपाय प्रदान करने वाला ऐसा कोई सामान्य प्रावधान आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित नहीं है। ऐसी त्रुटि सद्भावपूर्ण और अनजाने में प्रतीत होती है।

23. इस न्यायालय को आगे अवगत कराया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के कानून में, संबंधित प्रावधान भी धारा 6-ए है, जो विशेष रूप से संबंधित जिले के कलेक्टर को आवश्यक वस्तु को जब्त करने के साथ-साथ किसी भी जानवर, वाहन, पोत या अन्य परिवहन को जब्त करने की शक्ति सौंपता है, जिसका उपयोग ऐसी आवश्यक वस्तुओं को अवैध रूप से ले जाने में किया जाता है और कलेक्टर को अधिनियम के तहत जब्त की गई ऐसी चीजों के अधिग्रहण के लिए अधिकृत किया जाता है। उस अधिनियम में, धारा 6-सी धारा 6-ए के तहत पारित अधिग्रहण के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक

प्राधिकारी के समक्ष सांविधिक अपील का उपाय निर्धारित करती है। इस प्रकार, यह प्रचारित किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत भी जिला कलेक्टर द्वारा पारित अधिग्रहण के आदेश के खिलाफ अपील का सांविधिक उपाय भी उपलब्ध और विशेष रूप से निर्धारित है।

24. इस न्यायालय का ध्यान राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के संबंधित प्रावधान की ओर भी आकर्षित किया गया है, जिसमें धारा 52 यह परिकल्पित करती है कि जब यह मानने का कारण होता है कि किसी भी वन उपज के संबंध में एक अपराध किया गया है, तो ऐसी उपज के साथ सभी मशीनरी, गाड़ियां, उपकरण, नावें, वाहन, रस्सियां, चेन या ऐसे अपराध को करने में उपयोग की जाने वाली कोई भी अन्य वस्तु, किसी भी वन अधिकारी या एक पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त की जा सकती है, जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का नहीं है। ऐसी जब्त की गई वस्तुएं अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं और अधिग्रहण के आदेश के खिलाफ, धारा 52-ए मुख्य वन संरक्षक के समक्ष अपील का प्रावधान प्रदान करती है। इसके अलावा, पुनरीक्षण का उपाय भी अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है जैसा कि धारा 52-बी के तहत परिकल्पित है। इस प्रकार, राजस्थान वन अधिनियम में भी, अधिग्रहण का आदेश अपील और पुनरीक्षण के उपाय के उप-पाठ में है, जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित है।

25. ऊपर संदर्भित कानूनों के अलावा, यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में, गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 को हरियाणा राज्य की विधायिका द्वारा प्रख्यापित किया गया है। उस अधिनियम में भी, धारा 17 वाहनों के अधिग्रहण का प्रावधान निर्धारित

करती है और सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी अन्य अधिकारी जब्त किए गए वाहन को जब्त करने और अधिग्रहण का आदेश पारित करने के लिए अधिकृत है। उप-धारा (3) में, न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया गया है और केवल सक्षम प्राधिकारी को ऐसे जब्त किए गए वाहन के कब्जे, वितरण, निपटान, रिहाई के संबंध में आदेश देने का अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है। लेकिन धारा 17 की उप-धारा (5) अधिनियम की उप-धारा (2) और (4) के तहत अधिग्रहण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को संबंधित जिले के उपायुक्त के समक्ष अपील का उपाय प्रदान करती है। इस प्रकार, आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत संभागीय आयुक्त के समक्ष धारा 6-ए के तहत पारित आदेश के खिलाफ व्यथित व्यक्ति के लिए भी इसी तरह का उपाय खुला होना चाहिए।

26. विद्वान न्याय मित्र (Amicus Curiae) ने बताया है कि हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य के विधानमंडल द्वारा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 लागू किया गया है। उस अधिनियम में भी, धारा 17 वाहनों की जब्ती का प्रावधान करती है और सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जब्त किए गए वाहन को जब्त करने और उसकी जब्ती का आदेश पारित करने के लिए अधिकृत है। उप-धारा (3) में, न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया गया है और केवल सक्षम प्राधिकारी को ही ऐसे जब्त किए गए वाहन के कब्जे, सुपुर्दगी, निपटान, रिहाई के संबंध में आदेश देने का क्षेत्राधिकार सौंपा गया है। लेकिन धारा 17 की उप-धारा (5) किसी भी व्यक्ति को जो उप-धारा (2)

और (4) के तहत जब्ती के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित है, संबंधित जिले के उपायुक्त के समक्ष अपील का उपाय प्रदान करती है। इस प्रकार, आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत धारा 6-ए के तहत पारित आदेश के खिलाफ व्यथित व्यक्ति के लिए संभागीय आयुक्त के समक्ष इसी तरह का उपाय खुला होना चाहिए।

27. उपरोक्त संदर्भित अन्य केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और कानूनों, जो समान विषय वस्तु से संबंधित अन्य राज्यों में लागू हैं और कानून के विशेष वैधानिक प्रावधानों के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा वाहन के साधन की जब्ती की कार्यवाही से संबंधित हैं, की प्रासंगिक प्रावधानों को देखने के बाद और आरबीए अधिनियम, 1995 में धारा 6-ए के संशोधित प्रावधान को शामिल करने के लिए राजस्थान के राज्य विधानमंडल द्वारा, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 में निहित प्रावधान के समान, वाहन के साधन की जब्ती और जब्ती के लिए प्रावधान प्रदान करने के उद्देश्य और कारणों के बयान को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाना और यह मानना मुश्किल है कि राज्य विधानमंडल ने, जानबूझकर और इरादतन, सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण का कोई विशिष्ट प्रावधान निर्धारित नहीं किया। साथ ही, यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 6-ए में ऐसे कोई शब्द निर्धारित नहीं हैं, जो उसमें पारित आदेश को कोई अंतिम रूप दें। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 6-ए को राज्य विधानमंडल द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन के साधन को भी जब्त करने और उसकी जब्ती की अनुमति देने के उद्देश्य से डाला गया था और धारा 6-ए के इस प्रावधान में, केवल सक्षम प्राधिकारी को जब्ती का आदेश देने का क्षेत्राधिकार सौंपा

गया है, साथ ही किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर, ऐसे वाहन के साधन के कब्जे, सुपुर्दगी, निपटान या रिहाई के संबंध में भी। निर्विवाद रूप से, सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर पहले से ही अधिनियम के तहत जब्त किए गए गोवंशीय पशुओं की हिरासत, सुपुर्दगी और निपटान से निपटने के लिए अधिकृत था और उसका क्षेत्राधिकार था, जिसके लिए आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत धारा 7 का प्रावधान परिकल्पित है। निस्संदेह, राज्य विधानमंडल ने किसी भी व्यथित व्यक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा जब्त किए गए गोवंशीय पशुओं के अस्थायी या स्थायी सौंपने के संबंध में धारा 7 की उप-धारा (1) या (2) के तहत पारित आदेश के खिलाफ, धारा 7 की उप-धारा (3) के आधार पर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील का प्रावधान निर्धारित किया है। अपील/पुनरीक्षण का उपाय ऊपर संदर्भित अन्य कानूनों के तहत भी उपलब्ध है। प्रश्न पर समग्र और व्यापक रूप से विचार करते हुए, किसी भी कल्पना से, धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील के प्रावधान को शामिल न करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार, किसी भी तरह से यह नहीं माना जा सकता है कि राज्य विधानमंडल व्यथित व्यक्ति को धारा 6-ए के तहत उसी सक्षम प्राधिकारी यानी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील का उपाय करने से वंचित करने के लिए इच्छुक था। राज्य विधानमंडल का ऐसा इरादा इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि धारा 6-ए के प्रावधान में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अंतिम और निर्णायक नहीं माना गया है।

28. इसलिए, धारा 6-ए और धारा 7 के प्रावधानों की शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करके दोनों प्रावधानों को एक साथ और संचयी रूप से

पढ़कर, साथ ही राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 के समान धारा 6-ए के प्रावधान को शामिल करने पर विचार करते हुए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि राज्य विधानमंडल का कभी भी यह इरादा नहीं था कि धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कोई अंतिम रूप दिया जाए और अधिनियम में उसके खिलाफ अपील या पुनरीक्षण का कोई उपाय प्रदान न किया जाए। इस न्यायालय की राय में, आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी, यानी जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को भी धारा 7(1) या (2) के तहत पारित कलेक्टर यानी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ धारा 7(3) के तहत अपील के उपाय की उपलब्धता के समान तरीके से, संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती देने योग्य होना चाहिए।

29. फिर भी, यह एक साथ सच है कि धारा 6-ए के प्रावधान में या आरबीए अधिनियम, 1995 के किसी अन्य वैधानिक प्रावधान में, जब्ती के संबंध में धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण के उपाय की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट शब्दों में आवश्यक वैधानिक शब्द, या वाहन के साधन के कब्जे, सुपुर्दगी, निपटान या रिहाई के संबंध में कोई आदेश देने के लिए, चाहे वह संभागीय आयुक्त के समक्ष हो या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष, कानून में परिलक्षित या स्थान नहीं पाते हैं। यह कमी/खामी एक आकस्मिक चूक का मामला हो सकती है, न कि जानबूझकर बहिष्करण का, फिर भी इस न्यायालय की राय में, इसे न्यायालय द्वारा न तो संभागीय आयुक्त को अपील के क्षेत्राधिकार को ग्रहण करने के लिए निहित शक्तियों के सिद्धांत को लागू करके भरा जा सकता है और न ही उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

और कैसस ओमिशन (casus omissus) के सिद्धांतों को लागू करके। यह न्यायालय कानून के अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव से सहमत है कि अपील का अधिकार तब तक मौजूद नहीं माना जा सकता है जब तक कि कानून के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो।

30. इसलिए, आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्ति और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा पारित impugned आदेशों के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण के किसी भी वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बारे में उपरोक्त कानूनी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है, हालांकि, समान प्रकृति के विषय वस्तु से निपटने वाले उपरोक्त संदर्भित अन्य कानूनों में प्रदान किए गए जब्ती के आदेश और अन्य प्रकार के सहायक आदेशों के खिलाफ वैधानिक उपाय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपनी राय दर्ज करता है कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण का एक उपाय व्यथित व्यक्ति के लिए खुला होना चाहिए और प्रदान किया जाना चाहिए। यह एक नजरअंदाज नहीं होना चाहिए कि उसी सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा धारा 7(1) या (2) के तहत पारित आदेश के खिलाफ, धारा 7(3) के तहत संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील का उपाय पहले से ही निर्धारित है, जितना कि राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में भी, धारा 69(4) के तहत पारित जब्ती के आदेश के खिलाफ, धारा 9-ए के तहत अपील का उपाय उपलब्ध है। आरबीए अधिनियम, 1995 में राज्य विधानमंडल द्वारा धारा 6-ए का प्रावधान राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 69 के समान तर्ज पर, अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से, आरबीए अधिनियम के तहत

अपराध करने में इस्तेमाल किए गए वाहन के साधन को भी जब्त करने और उसकी जब्ती के लिए डाला गया था। इसलिए, यह न्यायालय इसे उचित और सही मानता है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 के समान धारा 6-ए के प्रावधान को उसकी पूर्णता तक लाने के लिए, राज्य विधानमंडल को इस मुद्दे पर अपना ध्यान देना चाहिए कि धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ व्यथित व्यक्ति के लिए अपील का उपाय उसी तरह खोला जाए जैसा कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 7(3) के तहत धारा 7(1) या (2) के तहत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ उपलब्ध है और यह न्यायालय राजस्थान सरकार को इसकी सिफारिश करना उचित समझता है कि वह इस पर विचार करे और इस संबंध में कमी/खामी को भरने के लिए आगे बढ़े, या कम से कम इस संबंध में स्पष्टीकरण दे, यदि वह ऐसा करना अपने अधिकार क्षेत्र में और अपनी समझ के अनुसार उचित और सही समझती है।

31. दूसरे मुद्दे पर आते हुए, जो सीआरपीसी (Cr.PC) की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में आक्षेपित (Impugned) आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और दायरे से संबंधित है, रिकॉर्ड से यह पाया गया है कि आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2097/2024, 1978/2024 और 6030/2023 में, क्रमशः 05.07.2023, 20.02.2024 और 03.08.2023 के आक्षेपित आदेशों द्वारा, सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों में, आरबीए अधिनियम, 1995 (RBA Act, 1995) की धारा 6-ए के तहत वाहनों (means of conveyance) को जब्त करने का आदेश दिया गया है और वाहनों को अंतरिम हिरासत में छोड़ने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा की

गई प्रार्थना को कलेक्टर ने खारिज कर दिया है। आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1941/2024 में, 20.03.2024 के आक्षेपित आदेश के तहत, जिला कलेक्टर ने, हालांकि, वाहन को याचिकाकर्ता को सुपुर्दगी पर छोड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन वाहन की जब्ती का कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

32. आक्षेपित आदेशों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के मुद्दे से निपटने के लिए, यह जांचना वांछनीय और आवश्यक है कि क्या संबंधित जिला कलेक्टर, जो सक्षम प्राधिकारी है, ने आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय एक आपराधिक न्यायालय की तरह कार्य किया है या किसी अन्य क्षमता में? इस संदर्भ में, यह उजागर करना उपयोगी और योग्य होगा कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए की उप-धारा (3) के तहत, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है और अधिकार क्षेत्र को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित सक्षम प्राधिकारी को ही सौंपा गया है, ताकि वाहन के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई के संबंध में आदेश दिया जा सके, इसके अलावा, यदि यह पाया जाता है कि वाहन का उपयोग अधिनियम के तहत अपराध करने में किया गया था, तो उसे जब्त करने का अधिकार भी इसी के पास है। इस प्रकार, आरबीए अधिनियम, 1995 में, संबंधित जिले के कलेक्टर, जहां अपराध किया गया है और उसमें इस्तेमाल किया गया वाहन जब्त किया गया है, को जब्ती की कार्यवाही को आगे बढ़ाने और समाप्त करने और अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए जब्त किए गए वाहन के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई से संबंधित मामले से निपटने के लिए अधिकृत किया गया है।

33. याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना है कि, अपने संबंधित वाहनों (वाहन) के पंजीकृत मालिक होने के नाते, जिसे आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध करने के संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करते समय पुलिस द्वारा जब्त किया गया था, संबंधित प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक मामले के मुकदमे के समापन तक कम से कम वाहन को अंतरिम हिरासत में या सुपुर्दगी पर याचिकाकर्ताओं को छोड़ने का आदेश दिया जाए और उनका निवेदन है कि आपराधिक मामले के मुकदमे के दौरान, वाहन को सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा जब्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका तर्क है कि यहां किसी भी मामले में, वाहन को आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 12-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया था, बल्कि याचिकाकर्ताओं के वाहनों को पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था, जबकि आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध (अपराधों) को करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह आरोप लगाया गया था कि वाहन का उपयोग अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया जा रहा था। इसलिए, उनका निवेदन है कि, जब तक आपराधिक न्यायालय के समक्ष आपराधिक मुकदमे में अपराध का कमीशन और ऐसे अपराध में वाहन का उपयोग साबित नहीं हो जाता है, तब तक जब्त करने वाला प्राधिकारी केवल प्राथमिकी दर्ज करने और पुलिस द्वारा उस प्राथमिकी के संबंध में वाहन को जब्त करने के कारण इस निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए कि वाहन का उपयोग अधिनियम के तहत अपराध करने में किया गया था। उनका तर्क है कि चूंकि वाहन की जब्ती पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के आधार पर की गई थी, न कि सक्षम या जब्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वयं, ऐसे तथ्यात्मक परिदृश्य में, वाहन की जब्ती की कार्यवाही को आपराधिक

मामले के सबूत के लिए आकस्मिक और सहायक माना जाना चाहिए। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इन याचिकाओं को दाखिल करके, याचिकाकर्ताओं ने आक्षेपित आदेशों को रद्द करने और अपने संबंधित वाहनों को अंतरिम हिरासत में या सुपुर्दगी पर उचित शर्तों और नियमों पर तब तक छोड़ने का निर्देश देने की प्रार्थना की है जब तक कि संबंधित प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक मामले का मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता, जिसमें उनके वाहन पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे।

34. इसके विपरीत, राज्य की ओर से और राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान लोक अभियोजक ने याचिकाओं का विरोध किया है और तर्क दिया है कि जिला कलेक्टर, जिसे राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित सक्षम प्राधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है, को इस अधिनियम के तहत अपराध करने में उपयोग किए गए वाहन को जब्त करने के लिए धारा 6-ए के आधार पर अधिकृत किया गया है और जब्त करने का उनका अधिकार क्षेत्र, आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत कथित अपराधों को करने के लिए अपराधी को दंडित करने या न करने के लिए आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र, अलग और पृथक है। उनका तर्क है कि जब्त करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य के बावजूद किया जा सकता है कि आपराधिक अभियोजन शुरू हुआ है या नहीं। विद्वान लोक अभियोजक ने इस न्यायालय का ध्यान धारा 6-ए की उप-धारा (5) की ओर आकर्षित किया है, जो यह निर्धारित करती है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया जब्ती का आदेश किसी भी दंड को लागू होने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी है। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जब्ती के आक्षेपित आदेश प्रकृति में अंतिम हैं

और राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में जिला कलेक्टर द्वारा अधिकार क्षेत्र के भीतर पारित किए गए हैं, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहनों को छोड़ने से इनकार करने का आदेश भी उचित है, जिस पर आपराधिक विविध याचिका संख्या 1941/2024 में सवाल उठाया गया है। इसलिए, विद्वान लोक अभियोजक के अनुसार, आक्षेपित आदेश न्याय के गर्भपात का कारण नहीं बनते हैं, बल्कि कलेक्टर द्वारा अपनी अधिकारिता के प्रयोग के भीतर, जब्त करने वाले प्राधिकारी के रूप में पारित किए गए हैं, इसलिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

35. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम कल्लो बाई [(2017) 14 SCC 502]

के मामले में, मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969, को वन अधिनियम, 1927 के साथ पढ़कर, अनाधिकृत रूप से सागौन की लकड़ी के परिवहन में शामिल पाए गए वाहन की जब्ती का मुद्दा, जो जब्त किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। संबंधित वन प्रभाग के वन अधिकारी-सह-उप-विभागीय अधिकारी ने आपराधिक मामले के आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही से अलग, जब्त किए गए वाहन की जब्ती की कार्यवाही शुरू की और अंत में वन अधिकारी द्वारा वाहन की जब्ती का आदेश दिया गया। वाहन के व्यथित मालिक ने कानून के तहत प्रदान की गई अपील दायर की, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी-सह-मुख्य वन संरक्षक ने जब्ती के आदेश की पुष्टि की। फिर, व्यथित व्यक्ति ने अधिनियम, 1969 की धारा 15-बी के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण (revision) दायर किया। पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया गया और जब्ती के आदेश को रद्द करते हुए, अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश ने वाहन को छोड़ने का निर्देश दिया, जिसके खिलाफ राज्य ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और इस प्रकार, मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम 1969 की धारा 15 पर विश्लेषणात्मक चर्चा के बाद, जो जब्ती के लिए उत्तरदायी संपत्ति की तलाशी और जब्ती और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है, यह माना कि धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत, संबंधित वन अधिकारी अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तलाशी लेने के लिए सशक्त है और उप-धारा (2) के तहत, संबंधित अधिकारी वाहन, रस्सियों आदि को जब्त कर सकता है यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि उक्त वस्तुओं का उपयोग अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया गया था। यह देखा गया कि उप-धारा (3) जब्त की गई वस्तुओं की जब्ती के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है और जब्ती का आदेश पारित करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, जैसा कि जब्ती प्राधिकारी को वन अपराध के कमीशन के संबंध में संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता थी। अधिनियम की धारा 15-सी भी अदालतों और न्यायाधिकरण पर वस्तु को जारी करने पर क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाती है, यदि अधिनियम की धारा 15 के तहत जब्ती की कार्यवाही शुरू की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना और देखा कि अधिनियम की धारा 15 के तहत परिकल्पित जब्ती की कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है न कि आपराधिक कार्यवाही, जो अपराध करने के लिए न्यायालय के समक्ष मुकदमे से अलग और विशिष्ट कार्यवाही हैं। निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा, यानी पैरा संख्या 18, 22, 23 और 24, को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"18. अधिनियम की व्यापक योजना उन लोगों को आपराधिक अदालत के हाथों कानून के उल्लंघन के लिए दंडित करना है। जब्ती सजा के लिए आकस्मिक और सहायक होने के कारण, मध्य प्रदेश राज्य ने जब्ती की प्रक्रिया को अभियोजन की प्रक्रिया से अलग कर दिया। अधिनियम का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि संपत्ति के निपटान के संबंध में आपराधिक अदालत की शक्ति को उस पहलू के संबंध में अधिकृत अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अधीन किया जाता है; मुख्य मुकदमे के संबंध में आपराधिक अदालत का क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहता है।

22. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि धारा 15 संबंधित प्राधिकारी को अपराध पूरी तरह से स्थापित होने से पहले भी, वहां उल्लिखित लेखों को जब्त करने की स्वतंत्र शक्ति देती है। इस शक्ति का प्रयोग संबंधित अधिकारी द्वारा किया जा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उक्त वस्तुओं का उपयोग वन अपराध के कमीशन के दौरान किया गया था। वाहनों/वस्तुओं के मालिकों के लिए एक सुरक्षा प्रदान की जाती है, यदि वे यह साबित करने में सक्षम हैं कि उन्होंने अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत परिकल्पित सभी उचित देखभाल और सावधानी बरती और उक्त अपराध उनकी जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था।

23. आपराधिक अभियोजन जब्ती की कार्यवाही से अलग है। दोनों कार्यवाही अलग और समानांतर हैं, प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब्ती कार्यवाही का उद्देश्य अपराध करने के लिए उपयोग किए गए उपज और साधनों की जब्ती के संबंध में त्वरित और प्रभावी न्यायनिर्णयन को सक्षम करना है, जबकि अभियोजन का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना है। अधिनियम की योजना जब्ती के लिए एक स्वतंत्र प्रक्रिया निर्धारित करती है। अलग-अलग कार्यवाही निर्धारित करने का इरादा एक निवारक तंत्र प्रदान करना और वाहन के आगे के दुरुपयोग को रोकना है।

24. पुनरावृत्ति की लागत पर हम स्पष्ट करते हैं कि जब्ती की कार्यवाही मुख्य आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र है। पिछले पैराग्राफ में हमारी विस्तृत चर्चा के मद्देनजर, हम इस राय के हैं कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि जब तक आरोपी का अपराध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाता, तब तक कानून के तहत जब्ती की अनुमति नहीं थी।"

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक और मामले में, यानी **अब्दुल वहाब बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2022) 13 SCC 310]**, अपीलकर्ता के ट्रक की जब्ती का आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 11(5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, यहाँ तक कि आपराधिक मामले से आरोपियों के बरी होने के बाद भी। जब्ती के आदेश की अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पुष्टि की गई थी और उसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका भी उच्च न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष ट्रक मालिक द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका भी खारिज कर दी गई थी, जिसमें जब्ती के आदेश की पुष्टि की गई थी और यह माना गया था कि जिला मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मामले से आरोपियों के बरी होने के बाद भी, ट्रक की जब्ती का आदेश पारित करने में कोई गलती नहीं की थी। इस प्रकार, मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया कि उच्च न्यायालय ने **कल्लो बाई (सुप्रा)** के फैसले पर भरोसा करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित जब्ती के आदेश को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि अपराध करने के लिए उपयोग किए गए वाहनों/उपकरणों की जब्ती की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अलग से जारी रखने योग्य है, जो अपराध के आरोपी के अभियोजन की कार्यवाही से अलग है और आपराधिक न्यायालय के समक्ष शुरू होती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना और देखा कि यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्ती की कार्यवाही आपराधिक अभियोजन से अलग है और दोनों कार्यवाही एक साथ चल सकती हैं, लेकिन ऐसे मामले में जहां अपराधी/आरोपी आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाते हैं, आपराधिक मुकदमे में दिए गए निर्णय को

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्ती की कार्यवाही पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। अंत में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया, यह मानते हुए कि जिला मजिस्ट्रेट का जब्ती आदेश कायम नहीं रह सकता है और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का निर्णय भी रद्द कर दिया गया। निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को, यानी पैरा संख्या 17 से 22, को नीचे पुनरुत्पादित करना उचित होगा:

"17. जब्ती के आदेश के कारण, एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति के उपभोग से वंचित कर दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 300 ए यह प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए, राज्य के लिए, अन्य बातों के अलावा, यह स्थापित करना आवश्यक है कि संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की गई थी या अपराध की आय का हिस्सा है या सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक हित के लिए वंचित करना आवश्यक है।

18. इस स्तर पर, हम स्टेट ऑफ डब्ल्यू.बी. बनाम सुजीत कुमार राणा [(2004) 4 SCC 129] में इस न्यायालय की राय का उपयोगी संदर्भ दे सकते हैं। यहां वन अधिनियम, 1927 (और डब्ल्यू.बी अधिनियम 22, 1988 के तहत प्रासंगिक प्रविष्टि) जैसे सार्वजनिक हित में बनाए गए कानूनों और उनसे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाही, जो किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करती है, के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। तदनुसार, यह देखा गया कि "एक अपराध का कमीशन" जब्ती का आदेश पारित करने के लिए आवश्यक अवयवों में से एक है और 7 (2004) 4 SCC 129 जब्ती का आदेश स्वचालित रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित है:

"26. अधिनियम की धारा 59-ए के तहत एक कार्यवाही में वन उपज की जब्ती का आदेश न तो दंड के बराबर होगा और न ही सजा के। हालांकि, ऐसा आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब एक वैध जब्ती की गई हो और अधिकृत अधिकारी स्वयं को राज्य में वन उपज के स्वामित्व के साथ-साथ वन अपराध के कमीशन के संबंध में संतुष्ट करे। जब्ती का आदेश स्वचालित रूप से पारित नहीं किया जाना है, और धारा 59-ए की उप-धारा (3) के

अनुसार एक विवेकाधीन शक्ति वाहन के संबंध में अधिकृत अधिकारी को प्रदान की गई है। धारा 59-ए की उप-धारा (3) के अनुसार साबित होने के लिए आवश्यक अवयवों के अलावा, धारा 59-बी से जुड़ी शर्त के कारण, वाहन के मालिक को भी एक नोटिस जारी करना आवश्यक है और इसके अलावा उसकी उप-धारा (2) के अनुसार वाहन के मालिक को यह दिखाने में सक्षम बनाने के लिए एक अवसर दिया जाना है कि इसका उपयोग उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना वन उपज ले जाने के लिए किया गया था और आवश्यक रूप से इसके लिए सावधानियां बरती गई हैं।”

19. जहां तक राज्य के वकील के इस तर्क का सवाल है कि जब्ती की प्रक्रिया में सबूत का बोझ ट्रक मालिक पर है, हमें यह बताना होगा कि 2004 के अधिनियम की धारा 13 ए, जो सबूत का बोझ बदल देती है, जब्ती की कार्यवाही के लिए नहीं बल्कि अभियोजन की प्रक्रिया के लिए लागू होती है। 2004 के अधिनियम की धारा 13 ए के आधार पर, जब्ती के आदेश को कानूनी रूप से सही ठहराने के लिए राज्य प्राधिकारी पर बोझ, जब्ती की कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। राज्य के वकील के विपरीत तर्क को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

20. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के ट्रक को अकेले आपराधिक कार्यवाही के कारण जब्त किया गया था और इसलिए, लागू कानून के तहत, वाहन को राज्य द्वारा तब रोका और जब्त नहीं किया जा सकता, जब मूल कार्यवाही बरी होने में समाप्त हो गई हो। यह भी अनुमानित मामला नहीं है कि अपीलकर्ता के ट्रक का उपयोग इसी तरह के अपराध को करने के लिए किया जाएगा।

21. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2004 के अधिनियम का उद्देश्य दंडात्मक और निवारक प्रकृति का है। 2004 के अधिनियम की धारा 11 और एम.पी. गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 के नियम 5, धारा 4, 5, 6, 6 ए और 6 बी के उल्लंघन के मामले में वाहन की जब्ती और जब्ती की अनुमति देते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्ती की कार्यवाही आपराधिक अभियोजन से अलग है। हालांकि, दोनों एक साथ चल सकती हैं, ताकि अपराध करने के लिए उपयोग किए गए साधनों की जब्ती के संबंध में त्वरित और प्रभावी न्यायनिर्णयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट के पास 2004 के अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 6 ए और 6 बी के तहत उल्लंघनों के मामलों का स्वतंत्र रूप से न्यायनिर्णयन करने और उल्लंघन के मामले में जब्ती का आदेश पारित करने की शक्ति है।

लेकिन ऐसे मामले में जहां अपराधी/आरोपी आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाते हैं, आपराधिक मुकदमे में दिए गए निर्णय को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्ती की कार्यवाही का निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, बरी होने का आदेश इसलिए पारित किया गया था क्योंकि आरोपी को आरोपों से जोड़ने के लिए सबूत गायब थे। आपराधिक अभियोजन में बरी होने पर अपीलकर्ता के ट्रक की जब्ती, उसकी संपत्ति के मनमाने ढंग से वंचित होने के बराबर है और अनुच्छेद 300 ए के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करती है। इसलिए, यहां की परिस्थितियां यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करती हैं कि जिला मजिस्ट्रेट का जब्ती का आदेश (परीक्षण न्यायालय के बरी होने के फैसले की अनदेखी करते हुए), न केवल मनमाना है बल्कि कानूनी आवश्यकताओं के साथ भी असंगत है।

22. उपरोक्त के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट का जब्ती आदेश कायम नहीं रह सकता है और ऐसा ही घोषित किया जाता है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का इसके विपरीत निर्णय रद्द किया जाता है। यह अपील बिना किसी लागत के इस आदेश के साथ स्वीकार की जाती है।"

(जोर दिया गया)

37. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में 26.02.2024 को एक आदेश पारित किया है; विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1910/2024 [MANU/SCOR/31464/2024], जिसमें राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 3, 5, 6, 8, 9 और 10 के तहत अपराधों के संबंध में जब्त किए गए वाहन की जब्ती के आदेश को आपराधिक मामले के मुकदमे के दौरान प्रभावी नहीं होने का निर्देश दिया गया था और वाहन को सुपुर्दगी पर आपराधिक मामले के अंतिम परिणाम के अधीन छोड़ने की अनुमति दी गई थी।

"उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका को खारिज करने वाले 17.05.2023 के आदेश से उत्पन्न,

जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के 23.09.2021 के आदेश की पुष्टि करते हुए, जिसमें राजस्थान गोजातीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी प्रवास या निर्यात विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 3, 5, 6, 8, 9 और 10 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 के तहत दर्ज अपराधों के तहत जब्त किए गए वाहन को जब्त करने का निर्देश दिया गया था। थाना कोतवाली जालौर, राजस्थान की एफआईआर संख्या 174/2021 के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ऐसे वाहन को छोड़ने से इनकार कर दिया गया था और कथित रूप से अपना अपराध साबित कर दिया गया था। पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मामले के तथ्यों में निर्देश देते हैं कि मुकदमे के दौरान, वाहन की जब्ती का आदेश प्रभावी नहीं होगा और प्रश्नाधीन वाहन, ट्रक टाटा एलपी संख्या आरजे 14 जीएच 4462 आपराधिक मामले के अंतिम निर्णय के अधीन और 2 लाख रुपये की बैंक गारंटी और शेष राशि की जमानत प्रस्तुत करने पर, जिसका वाहन दुर्घटना की तिथि पर बीमाकृत था और ऐसी अन्य शर्तों पर जारी किया जाएगा जो जब्ती अधिकारी द्वारा लगाई जा सकती हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, विचाराधीन वाहन आज से दो सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुसार, इस स्तर पर आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।”

38(i). माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेश से, जिनका यहां उल्लेख किया गया है, और आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन को जब्त करने के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि जब भी पुलिस द्वारा आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध करने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करते समय वाहन को जब्त किया जाता है, तो ऐसे वाहन की जब्ती की कार्यवाही, यदि सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शुरू की जाती है, तो आपराधिक मामले के अंतिम

निष्कर्ष के लिए आकस्मिक और सहायक होगी, हालांकि, स्थिति उस मामले में भिन्न हो सकती है, जहां सक्षम प्राधिकारी आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 12-ए के संशोधित प्रावधान के तहत अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में वाहन को जब्त करता है, और आपराधिक मामला बाद में दर्ज किया जाता है या यहां तक कि दर्ज नहीं भी किया जा सकता है।

38(ii). इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब्ती की कार्यवाही, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू और समाप्त की जाती है, आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र, विशिष्ट/विभिन्न और अलग है, जो आपराधिक न्यायालय के समक्ष शुरू और समाप्त की जाती है, जब भी आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध करने के संबंध में एक प्राथमिकी अलग से दर्ज की जाती है। फिर भी, यह न्यायालय मानता है कि "आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत दंडनीय अपराध का कमीशन", धारा 6-ए का एक आवश्यक और अपेक्षित घटक है और अधिनियम के तहत जब्त किए गए किसी भी वाहन की जब्ती का अंतिम आदेश पारित करने से पहले, जब्त करने वाले प्राधिकारी को इस आशय का एक निष्कर्ष और संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता होती है कि जब्त किए गए वाहन का उपयोग अधिनियम के तहत ऐसे अपराध को करने में किया गया था। अपराध करने में जब्त किए गए वाहन के उपयोग के बारे में जब्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज किए बिना, जब्ती का आदेश स्वचालित रूप से पारित नहीं किया जा सकता है, केवल आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज करने पर वाहन की जब्ती के कारण।

38(iii). इस न्यायालय का यह भी विचार है और वह मानता है कि, आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत परिकल्पित जब्ती

कार्यवाही की प्रकृति और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, यह अर्ध-न्यायिक प्रकृति की है न कि आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति की। इसलिए, इस कोण से और इस तरह के विचार में, सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिला कलेक्टर, धारा 6-ए के तहत अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और एक आपराधिक न्यायालय की तरह नहीं।

38(iv). इस प्रकार, एक अपरिहार्य निष्कर्ष सामने आता है कि जबकि यह सच है कि जल्त करने की कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही से अलग, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वतंत्र रूप से बनाए रखने योग्य है, हालांकि, सक्षम प्राधिकारी को जल्ती की कार्यवाही को सावधानी से शुरू और समाप्त करना चाहिए, वाहन की जल्ती की मूल उत्पत्ति पर विचार करते हुए और यदि पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करते समय, आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध करने के संबंध में वाहन को जल्त किया गया था और आपराधिक न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामले का मुकदमा लंबित है, तो आपराधिक मुकदमे में दिए गए फैसले को जल्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अब्दुल वहाब (सुप्रा)** के मामले में देखा और माना है।

38(v). जहां तक अंतरिम हिरासत पर ऐसे वाहन के कब्जे, वितरण और निपटान या रिहाई के संबंध में आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का संबंध है, प्राधिकारी कानून के अनुसार ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो न्यायिक मिसालों के कानून द्वारा विधिवत निर्देशित हो, जो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में तय किए गए हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि पुलिस

स्टेशन के परिसर में लंबे समय तक वाहन को रोकना किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता है और यह न केवल मालिक को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि राज्य के खजाने को भी राजस्व का नुकसान पहुंचाएगा।

39. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग एक न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के संबंध में किया जा सकता है; जिसका आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में "एक आपराधिक न्यायालय" होगा या जहां शक्ति का प्रयोग आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह अब और अधिक अनिर्णित (*res integra*) नहीं है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता में धारा 482 के प्रावधान को शामिल करके बचाया गया है, जिसका प्रयोग ऐसे आदेश (आदेशों) को करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के सिरो को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। कानून के इस तरह के सुस्थापित प्रस्ताव के मद्देनजर, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में, यह न्यायालय आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के दायरे में सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करना मुश्किल पाता है, क्योंकि जब एक बार यह माना गया है और ऊपर देखा गया है कि सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, एक आपराधिक न्यायालय की तरह कार्य नहीं करते हैं और इसके अलावा, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को भी आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए की उप-धारा

(3) के तहत स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, तो उच्च न्यायालय के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में ऐसे प्राधिकारी के आदेश के साथ हस्तक्षेप करना समीचीन नहीं होगा।

40. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में, याचिकाकर्ताओं को अंतरिम हिरासत पर वाहनों को छोड़ने की अनुमति देना और आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता, **स्टेट ऑफ डब्ल्यू.बी. बनाम सुजीत कुमार राणा [(2004) 4 SCC 129]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुपात निर्णय (ratio decidendi) को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उस मामले में, वन उपज और उन्हें ले जाने वाले वाहनों को वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था। जब्त किए गए वाहनों की जब्ती की कार्यवाही वन अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 59-जी के तहत शुरू की गई थी, जिसे अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है और इस संबंध में आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अधिनियम के तहत बाहर रखा गया है, हालांकि, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में, वाहन को छोड़ने का निर्देश दिया था। तथ्यों की उस पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 33 और 46 में निम्नलिखित निर्णय दिया और टिप्पणी की:-

"33. उपर्युक्त प्रावधान के मात्र अवलोकन से, यह स्पष्ट होगा कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति केवल उस मामले में ही सुरक्षित है जहाँ आपराधिक न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो जिसे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रद्द किया जाना आवश्यक हो या जहाँ किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो। इसलिए, यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के संबंध में किया जा सकता है; जिसका दंड

प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में अर्थ होगा 'एक आपराधिक न्यायालय' या जहाँ से दंड संहिता के तहत न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति। प्रक्रिया। एक बार जब यह माना जाता है कि आपराधिक न्यायालय के पास अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्ति से निपटने की कोई शक्ति नहीं थी, तो उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कोई मामला नहीं बनता

46. हमारी उपर्युक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि एक बार जब जब्ती की कार्यवाही शुरू हो जाती है, तो अधिनियम की धारा 59-जी के अनुसार दंड न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निषिद्ध हो जाता है, उच्च न्यायालय भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता संपत्ति की अंतरिम रिहाई। उच्च न्यायालय ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के प्रयोग में ही कर सकता है।”

(ज़ोर दिया गया)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अब्दुल वहाब (सुप्रा)** के मामले में पैरा 18 में इस निर्णय पर भरोसा किया था, लेकिन एक अलग संदर्भ में यह माना कि "अपराध का होना" जब्ती आदेश पारित करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है और जब्ती आदेश स्वतः पारित नहीं होना चाहिए और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जनहित में बनाए गए वन अधिनियम, 1927 जैसे कानूनों और उससे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाहियों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। लेकिन जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का प्रश्न है, जो एक आपराधिक न्यायालय नहीं है और न ही प्राधिकरण द्वारा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पारित किया जाता है, पैरा संख्या 14 में इस निर्णय की पुनः पुष्टि की गई। इस प्रकार उसी सादृश्य को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत जब्त किए गए वाहन को छोड़ने का कोई निर्देश जारी

करना। 482 Cr.PC के तहत, जहाँ किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्जित है, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि धारा 482 Cr.PC के तहत उच्च न्यायालय द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध, यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई आपराधिक रिट याचिका में न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में, यानी **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह [(2020) 12 SCC 733]** के मामले में, यह माना गया था कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में मजिस्ट्रेट को जब्त वाहन को छोड़ने का निर्देश देने में त्रुटि की। चूंकि जब्ती की कार्यवाही वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 (3) के तहत शुरू की गई थी, हालांकि, कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित थी और इसलिए आपराधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र बाहर रखा गया था। उस मामले में, एमपी अधिनियम 25 के 1983 द्वारा प्रतिस्थापित वन अधिनियम, 1927 की योजना के अनुसार, धारा 52-सी (1) के मद्देनजर, एक बार विशेष कानून के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, आपराधिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह वन अधिकारी है जिसे वाहनों की अंतरिम हिरासत के लिए आदेश पारित करने की शक्ति निहित है और मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को दूर रखा गया है।

42. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित दो निर्णयों में प्रतिपादित सादृश्य और अनुपात निर्णय (ratio decidendi) को लागू करते हुए, और जब यह स्पष्ट है कि आरबीए अधिनियम, 1995 के विशेष कानून में भी, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है और अधिनियम की धारा 6-ए के तहत सौंपी गई अपनी विशेष शक्ति के भीतर अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन के कब्जे, वितरण, निपटान या रिहाई या जब्ती के संबंध में आदेश देने का अधिकार क्षेत्र केवल सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है, और यह न्यायालय पहले ही, पैरा संख्या 38 में, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि सक्षम प्राधिकारी धारा 6-ए के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एक आपराधिक न्यायालय की तरह कार्य नहीं करता है, ऐसी स्थिति में एक स्वाभाविक परिणाम और निष्कर्ष सामने आता है कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी अधिकारिता के प्रयोग में सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यहां यह राय दी गई है और देखा गया है कि उच्च न्यायालय रिट याचिका में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों के प्रयोग में सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश (आदेशों) में छूट दे सकता है और हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए आक्षेपित आदेशों के खिलाफ आपराधिक रिट याचिका (याचिकाएं) को स्पष्ट रूप से बनाए रखा जा सकता है और मनोरंजन किया जा सकता है, जिसमें उच्च न्यायालय आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की योग्यता पर जांच कर सकता है।

43. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने से खुद को रोक रहा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि, यहां यह देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं के लिए उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति और अधिकारिता को लागू करना और यदि वे चाहें तो आक्षेपित आदेशों के खिलाफ आपराधिक रिट याचिका (याचिकाएं) दायर करना खुला है।

44. **निष्कर्ष:** यह न्यायालय अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है;

(i). कि राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत जब्ती की कार्यवाही की प्रकृति अर्ध-न्यायिक है न कि आपराधिक कार्यवाही, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिले का कलेक्टर, आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत कोई भी आदेश पारित करते समय, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है न कि एक आपराधिक न्यायालय के रूप में;

(ii). कि राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत कार्यवाही स्वतंत्र और विशिष्ट हैं, जो सक्षम प्राधिकारी यानी संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष अलग से बनाए रखने योग्य हैं, आपराधिक कार्यवाही के अलावा, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक न्यायालय के समक्ष आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध (अपराधों) को करने के लिए गलत काम करने वाले के खिलाफ शुरू की गई हैं। यह निष्कर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम कालो बाई [(2017) 14 SCC 502]** के मामले में प्रतिपादित अनुपात निर्णय पर आधारित है;

(iii). कि सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत जब्ती की कार्यवाही को सावधानी और विवेक के साथ शुरू और समाप्त करे, वाहन की जब्ती की मूल उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए, और यदि पुलिस द्वारा आरबीए अधिनियम, 1995 के तहत अपराध (अपराधों) को करने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करते समय वाहन को जब्त किया गया था और ऐसी प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले मामले का आपराधिक मुकदमा आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो आपराधिक न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को जब्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा निष्कर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अब्दुल वहाब बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2022) 13 SCC 310]** के मामले में की गई टिप्पणियों पर आधारित है;

(iv). कि जहां तक अंतरिम हिरासत पर ऐसे वाहन के कब्जे, वितरण और निपटान या रिहाई के संबंध में आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता के प्रयोग का संबंध है, प्राधिकारी इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में तय किए गए न्यायिक मिसालों के कानून द्वारा विधिवत निर्देशित कानून के अनुसार ऐसे आदेश पारित कर सकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि पुलिस स्टेशन के परिसर में लंबे समय तक वाहन को रोकना किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता है और यह न केवल मालिक को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि राज्य के खजाने को भी राजस्व का नुकसान पहुंचाएगा।

(v). कि राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 2 (जी) के तहत सक्षम प्राधिकारी होने के नाते जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के

खिलाफ, राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के तहत उसे विशेष रूप से सौंपी गई अपनी शक्ति और अधिकारिता के प्रयोग में, उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्राधिकारी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक आपराधिक न्यायालय की तरह कार्य नहीं किया। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय ने **स्टेट ऑफ डब्ल्यू.बी. बनाम सुजीत कुमार राणा [(2004) 4 SCC 129]** और **स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम उदय सिंह [(2020) 12 SCC 733]** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुपात निर्णय का पालन किया है, जिसका यहां उल्लेख किया गया है। फिर भी, यह देखा जा सकता है कि ऐसा निष्कर्ष उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए, व्यथित व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को लागू करना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत पारित ऐसे आदेशों को चुनौती देने के लिए, उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को लागू करना खुला है और इसके खिलाफ आपराधिक रिट याचिका निश्चित रूप से दायर की जा सकती है; और

(vi). कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ किसी भी वैकल्पिक वैधानिक उपाय या अपील या पुनरीक्षण की उपलब्धता के बारे में कानून के प्रश्न के संबंध में, इस न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त की है और वर्तमान निर्णय के पैरा संख्या 30 में राजस्थान सरकार को सिफारिशें की हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

"30. इसलिए, आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी शक्ति और अधिकारिता के प्रयोग में जिला कलेक्टर द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों के खिलाफ किसी भी वैकल्पिक उपाय या अपील या पुनरीक्षण की उपलब्धता के बारे में कानून के उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है, हालांकि, जब्ती के आदेश और अन्य प्रकार के सहायक आदेशों के खिलाफ, अपील/पुनरीक्षण के वैधानिक उपाय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त संदर्भित अन्य कानूनों में प्रदान किया गया है, जो समान प्रकृति के विषय वस्तु से निपटते हैं, यह न्यायालय अपनी राय दर्ज करता है कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 6-ए के तहत अपनी अधिकारिता के प्रयोग में सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण का एक उपाय व्यथित व्यक्ति के लिए खुला होना चाहिए और प्रदान किया जाना चाहिए। यह एक भूल नहीं हो सकती है कि उसी सक्षम प्राधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा धारा 7 (1) या (2) के तहत पारित आदेश के खिलाफ, अपील का उपाय पहले से ही अधिनियम की धारा 7 (3) के तहत प्रभागीय आयुक्त के समक्ष निर्धारित है, जितना कि राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में भी, धारा 69 (4) के तहत पारित जब्ती के आदेश के खिलाफ, अपील का उपाय धारा 9-ए के तहत उपलब्ध है। धारा 6-ए का प्रावधान राज्य विधायिका द्वारा आरबीए अधिनियम, 1995 में, राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 69 की तर्ज पर, अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ डाला गया था, ताकि वाहन की जब्ती और जब्ती भी हो सके, जिसका उपयोग आरबीए अधिनियम के तहत अपराध करने में किया गया था। इसलिए, यह न्यायालय इसे उचित और उचित मानता है कि धारा 6-ए के प्रावधान को उसकी पूर्णता में लाने के लिए, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 की तर्ज पर, राज्य विधायिका को धारा 6-ए के तहत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ व्यथित व्यक्ति को अपील का उपाय खोलने के मुद्दे पर अपना ध्यान देना चाहिए, जैसा कि आरबीए अधिनियम, 1995 की धारा 7 (3) के तहत धारा 7 (1) या (2) के तहत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ उपलब्ध है और यह न्यायालय इसे राजस्थान सरकार को इसकी सिफारिशें करना उचित पाता है कि वह इस पर विचार करे और इस संबंध में अंतर/कमी को भरने के लिए आगे बढ़े, या कम से कम इस संबंध में स्पष्टीकरण करे, यदि वह ऐसा करना उचित और उचित समझती है,

तो अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर और अपने स्वयं के विवेक के अनुसार।"

45. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस निर्णय की एक प्रति राजस्थान के प्रधान कानून सचिव को तुरंत भेजने का निर्देश दिया जाता है, जो इसे राजस्थान राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को प्रसारित करेगा और साथ ही राजस्थान सरकार को इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय के पैरा संख्या 30 में की गई राय और सिफारिशों के बारे में अवगत कराएगा, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके, हालांकि, राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट, 1995 की धारा 6-ए के प्रावधान में, उसमें पारित आदेश के खिलाफ किसी भी उपाय या अपील/पुनरीक्षण प्रदान करने के संबंध में, किसी भी संशोधन को करने या न करने, या कोई स्पष्टीकरण देने या न देने के लिए, यह राजस्थान सरकार और राज्य विधायिका के विशेष अधिकार क्षेत्र, विवेक, अधिकारिता और शक्तियों के भीतर होगा और इस संबंध में, राजस्थान सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होगी, जैसा कि वह अपने स्वयं के विवेक के अनुसार फिट और उचित समझती है।

46. निर्णय से अलग होने से पहले, यह न्यायालय बार के विद्वान सदस्यों के लिए भी प्रशंसा का एक निशान रिकॉर्ड पर रखता है, जिन्होंने इन याचिकाओं में एमिस क्यूरी के रूप में इस न्यायालय को अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान की।

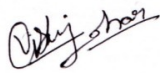
47. उपरोक्त टिप्पणियों, राय और सिफारिशों के साथ, लेकिन आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप किए बिना, इस सामान्य निर्णय द्वारा सभी चार वर्तमान आपराधिक विविध याचिकाओं का निपटान किया जाता है।

48. इस निर्णय की एक प्रति प्रत्येक संबंधित फाइल में रखी जाए।

(सुदेश बंसल),जे

सचिन

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़